an>

Title: The Minister of State in the Ministry of Parliamentary Affairs made a statement regarding Government Business during the week commencing the 14th March, 2017 and submissions made by Members.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI S.S. AHLUWALIA): With your permission, Madam, I rise to announce that Government Business during the week commencing Tuesday, the 14th of March, 2017 will consist of:-

1. Consideration of any items of Government Business carried over from today's order paper: - [**It contains Consideration and passing of the Admiralty (Jurisdiction and Settlement of Maritime Claims) Bill, 2016]**
2. Consideration and agreeing to the amendments made by Rajya Sabha in the Enemy Property (Amendment and Validation) Bill, 2016 as passed by Lok Sabha and as reported by Select Committee of Rajya Sabha, after it is passed by Rajya Sabha;
3. Discussion and voting on Demands for Grants for 2017-18 of the following Ministries:-

    (i) Railways

    (ii) Home Affairs

    (iii) Defence

    (iv) Agriculture

    (v) Coal

4. Presentation of the Third Supplementary Demands for Grants for 2016-17.

SHRI K. ASHOK KUMAR (KRISHNAGIRI): Sir, the following item may be taken for discussion during the next week business.

In my parliamentary constituency Krishnagiri, Denkanikottai is a backward area and Hosur is an industrial area. It is suitable for setting up of a NIPER and CIPET unit respectively.

The nationally recognized skill qualification training programs for providing skills that will secure a better livelihood in today's competitive work environment through better employment opportunities. The skill training offered is designed to tap the job potential of the growing industry and unemployed youth in my constituency.

HON. DEPUTY SPEAKER: Shri Prataprao Jadhav, are you not raising your submission?

श्री राम टहल चौधरी (राँची) : उपाध्यक्ष महोदय, अगले सप्ताह की कार्यवाही के दौरान मेरे निम्नलिखित एजेंडों को शामिल करने हेतु अनुमति पूदान करने की कृपा करें।

मेरे संसदीय क्षेत्र रांची में एयरपोर्ट के करीब मौजा हुण्डरु थाना डोरण्डा के गांववासियों की, जो रैयती जमीन हैं इस क्षेत्र में पिछड़े एवं गरीब लोग रहते हैं एवं आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र हैं। यहां के लोगों ने मुझे बताया है कि इस रैयती जमीन पर आर्मी के लोग गांव वालों को उनकी पूर्वज जमीन पर खेती नहीं करने दे रहे हैं। मेरी जानकारी में आया है कि आर्मी वाले ग्रामवासियों को धमकी देते हैं कि जमीन पर कोई खेती बाड़ी नहीं करेगा इस जमीन का मुआवजा आपको मिल जाएगा। इस संबंध में उपरोक्त गांव के लोगों को खेती करने एवं उनको सुरक्षित रहने के गारंटी के कार्य सदन की अगले सप्ताह में शामिल किया जाए।

दूसरा मेरे गृह राज्य झारखण्ड में दो सिंचाई परियोजनाएं चंडील बांध एवं ईचा बांध सिंचाई योजना है जिन्हें स्वर्ण रेखा परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। यह परियोजनाएं कई दशकों पूर्व शुरु की गई थीं और अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। इन परियोजनाओं से आपके रिकॉर्ड अनुसार 61 हजार लोग विस्थापित हुए। संसदीय क्षेत्र में यह परियोजना है जिसके कारण कई बार मैं इसका भ्रमण करने जाता हूं तो लोग मुआवजा, पुनर्वास एवं विकास पुस्तिका नहीं मिलने की बात करते हैं। इस पूकरण की जांच की जानी चाहिए। सदन की अगले सप्ताह की कार्यवाही में लोगों को पुनर्वास मुआवजा एवं विकास पुस्तिका दिलाए जाने एवं सिंचाई परियोजना की भूमि पर गांव के लोगों को कृÂिष कार्य करने हेतू भूमि पट्टे पर दिए जाने संबंधी भूमि पट्टे पर दी जाने के कार्य शामिल किया जाए।

श्री शैलेश कुमार (भागलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, कृपया निम्न दो विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में जोड़ लिया जाए।

आम नागरिकों को सुलभ न्याय दिलाये जाने को ध्यान में रखते बिहार राज्य के भागलपुर में पटना उच्च न्यायालय की एक स्थायी खंडपीठ की स्थापना किए जाने के संबंध में चर्चा कराए जाने की आवश्यकता।

बिहार राज्य के दर्जन भर से ज्यादा जिलों में करोड़ों लोगों के द्वारा बोले जाने वाली अंगिका भाषा को भारतीय संविधान की आठवीं अनुसुची में शामिल किए जाने के संबंध में चर्चा कराऐ जाने की आवश्यकता।

श्री विद्युत वरन महतो (जमशेदपुर): महोदय, मैं अनुरोध करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र के लोकमहत्व के निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्य सूची में शामिल किया जाए।

जमशेदपुर के अंतर्गत जुगसलाई आर.ओ.बी., जिसे पांच वÂर्ष पूर्व ही स्वीकृति मिल चुकी है एवं राज्य सरकार अपनी सहभागिता भी पूदान कर चुकी है तथा जमीन भी उपलब्ध करा दी गई है। फिर भी रेल विभाग द्वारा अभी तक किसी पूकार के काम को शुरू नहीं किया गया है, रेलवे के पदाधिकारी ढुलमुल रवैया अपनाते हुए आर.ओ.बी. को सीधा बनाना चाहते हैं, जो कि असंभव है। रेलवे के अनुसार इसमें जमीन कम जरूर लगेगी, लेकिन सैकड़ों करोड़ों रुपये का नुकसान होगा। जनहित में इस नुकसान को बचाने हेतु राज्य सरकार एवं रेल मंत्रालय के बीच आर.ओ.बी. यू टर्न के लिए तय किया गया है, लेकिन रेल विभाग के अनुसार यू टर्न आर.ओ.बी. बनाने हेतु ज्यादा जमीन लगने के कारण रेलवे मंत्रालय के द्वारा सात करोड़ रुपये राज्य सरकार से डिमांड करने के पूश्न पर यह

कार्य लम्बित है। जबकि प्रत्येक दिन इस रूट पर 8 से 10 हजार लोगों का आवागमन होता है। यह लाइन काफी व्यस्त रहने के कारण 30-40 लोगों की प्रति वषÂ्ान लाइन पार करते वक्त मृत्यु हो जाती है।

अतः आपने आग्रह है कि उपर्युक्त विÂषय को देखते हुए जनहित में अविलम्ब जुगसलाई आर.ओ.बी. के कार्य को चालू किया जाए।

इसके अलावा जमशेदपुर के अंतर्गत जादुगोडा यू.सी.आई.एल. विगत तीन साल से प्रदूषण अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं मिलने के कारण बंद पड़ा हुआ है। यह देश की यूरेनियम सैक्टर की एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। इसलिए मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि जादुगोडा यू.सी.आई.एल. को पर्यावरण क्लीयरेन्स जल्द से जल्द मिले, ताकि राÂष्ट्र के विकास में जादुगोडा यू.सी.आई.एल. अपनी भागीदारी प्रदान कर सके।

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र मावल के अंतर्गत माथेरन हिल स्टेशन इको-सेंसिटिव जोन होने के कारण यहां के स्थानीय निवासी अपने पुराने मकानों की मरम्मत नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण वहां के लोग अपने पुराने घरों में रहने को मजबूर हैं। अतः इस क्षेत्र के निवासियों को अपने मकानों की मरम्मत किये जाने की अनुमति प्रदान की जाए।

मेरा दूसरा सबमिशन यह है कि माथेरन हिल स्टेशन पर्यटन के लिए प्रसिद्ध होने के कारण यहां प्रतिदिन बहुत से पर्यटक आते हैं और इको-सेंसिटिव जोन होने के कारण यहां पर्यटकों के लिए चलने वाली एक मात्र मिनी ट्रेन को कुछ समय पहले बंद कर दिया गया है। जिसके कारण यहां के स्थानीय निवासी अपने रोजगार खो रहे हैं और इसका पर्यटन पर भी बुरा असर पड़ रहा है। अतः इस मिनी ट्रेन को पुनः चालू करने के विषय को अगले सप्ताह की कार्य सूची में शामिल किया जाए।

श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल) : महोदय, निम्न विषयों को अगले सप्ताह की कार्य-सूची में शामिल किया जाए।

1. उत्तर बिहार के कोसी प्रमंडल के अंतर्गत सहरसा एवं वीरपुर में राज्य सरकार का हवाई अड्डा काफी पुराना है एवं यहां से छोटे विमानों का प्रचालन भी होता है। इस हवाई अड्डे का विस्तार एवं सौंदर्यीकरण कर वाणिज्यिक सेवा शुरू करने से इस क्षेत्र की जनता को सुविधा मिलने के साथ-साथ सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होगी। अतः सहरसा एवं वीरपुर हवाई अड्डे का विस्तार एवं सौंदर्यीकरण कर वाणिज्यिक सेवा शुरू करने हेतु सख्त नियम बनाया जाए।

2. मेरे संसदीय क्षेत्र सुपौल के जिला मुख्यालय में रेलवे का फाटक है। इस फाटक से सुपौल जिला के 75 प्रतिशत लोगों का आवागमन अपने दैनिक जरूरतों की पूर्ति के लिए लगा रहता है एवं इसी फाटक से दो राजपथ क्रमशः सुपौल से रानीगंज वाया पिपरा, त्रिवेणीगंज एवं सुपौल से भपटियाही वाया किशनपुर गुजरते हैं तथा इस फाटक के बगल में सुपौल का बड़ा अड्डा भी है। जिसके परिणामस्वरूप वहां भयंकर जाम लगा रहता है। ऐसी परिस्थिति में सुपौल के लोहिया नगर चौक से पिपरा एवं किशनगंज जाने वाली सड़क पर रोड ऊपरी पुल बनाना आवश्यक है। अतः सुपौल के लोहिया नगर चौक से पिपरा एवं किशनगंज जाने वाली सड़क पर सड़क ऊपरी पुल बनाने हेतु सख्त नियम बनाया जाए।

माननीय उपाध्यक्ष : श्री ओम बिरला -- उपस्थित नहीं।

श्री रत्न लाल कटारिया।

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला) : महोदय, मैं आदरणीय प्रधान मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि मानसून आने पर हमारे देश में जहां कृÂि‍ष क्षेत्र का काफी फायदा होता है, वहीं हर वÂर्ष जन-धन की व्यापक हानि होती है और कई राज्य बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। मैं मांग करता हूं कि मानसून आने से पहले युद्ध स्तर पर जल प्रबंधन व बाढ़ के खतरे को टालने के प्रबंध किये जाएं। मेरा अनुरोध है कि इस विषय को संसद की आगामी कार्यवाही में शामिल किया जाए।

मेरा दूसरा सबमिशन यह है कि चीन के बाद भारत तकरीबन 35 करोड़ इंटरनेट उपभोक्ताओं के साथ विश्व में तीसरे स्थान पर है। भारत में जिस तरह से इंटरनेट के जरिये जीवन में व्यापक बदलाव आ रहा है, उससे न केवल हमारे सूचना एवं शिक्षा के क्षेत्र में, बल्कि बैंकिंग और सरकारी सेवाओं तक इंटरनेट की सुलभ पहुंच महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मैं मांग करता हूं कि संसद की आगामी कार्यवाही में भारत में डिजिटल क्रांति के विषय को शामिल किया जाए।

डॉ. वीरेन्द्र कुमार (टीकमगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, कृपया अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषयों का समावेश किया जाएः-

1. मध्य प्रदेश के मेरे संसदीय क्षेत्र छतरपुर जिले में एन.टी.पी.सी. के शिलन्यास का कार्य सन् 2014 के लोक सभा चुनाव के पूर्व किया गया था, किंतु निर्माण कार्य में प्रगति काफी धीमी है। अतः पर्यावरण संबंधी स्वीकृति एवं अन्य बाधाओं को दूर कर शीघ्र कार्य प्रारंभ कराया जाए।

2. मध्य प्रदेश के बुंदेलखण्ड का टीकमगढ़-छतरपुर क्षेत्र चिकित्सा सुविधाओं की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। मेडिकल कॉलेजों के दूर होने से बड़ी संख्या में मरीजों को जान से हाथ धोना पड़ता है। अतः टीकमगढ़-छतरपुर में केंद्र सरकार द्वारा मेडिकल कॉलेज खोलने की शीघ्र कर्रवाई की जाए।

श्री प्रतापराव जाधव (बुलढाणा) : उपाध्यक्ष महोदय, कृपया अगले सप्ताह की कार्यवाही के दौरान मेरे निम्नलिखित एजेंडों को शामिल करने हेतु अनुमति प्रदान करने की कृपा करेः-

1. देश के अकुशल मजदूरों को खेती में लगाकर उनको मनरेगा के अंतर्गत पूरे सौ कार्य-दिवस उपलब्ध कराने और देश के उत्पादन को बढाने के लिए मनरेगा को कृÂि‍ष के साथ जोडने एवं उनको वेतन मनरेगा द्वारा दिए जाने के कार्य।

2. कृषि के हर क्षेत्र में उन्नत इज़रायल की तरह देश में कृÂि‍ष उत्पादन को बढाने के लिए आधुनिक तकनीक द्वारा कृÂि‍ष कार्य करने हेतु किसानों को कौशल विकास अंतर्गत प्रशिक्षण दिए जाने का कार्य किया जाय, जिससे कम से कम भूमि पर अधिक से अधिक उत्पादन किया जा सके।